THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir.

(b) No. Sir.

(c) Does not arise.

क्षेत्र ग्रामीण बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के प्रतिसंदाय की निम्न प्रतिशतता

2292. श्री राम जेठमलानी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत वर्षों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के प्रतिसंदाय की प्रतिशतता कम रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऋण प्रतिसंदाय की दर क्या रही है;

(ग) क्या यह सच है कि इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लगभग 625 करोड़ रुपये की हानि हुई है; यदि नहीं, तो तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस हानि के कारणों का विश्लेषण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो वे कारण क्या हैं और ऋणों का प्रतिसंदाय न होने की वजह से उक्त अवधि के दौरान कितनी प्रतिशत ऋण राशि को बट्टे खाते में डालने का निदेश दिया गया?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि वर्ष 1992-93 से 1994-95 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वसूली निष्पादन में सुधार हुआ है। उक्त अवधि में मांग के संदर्भ में वसूली प्रतिशत निम्नलिखित रहा :—

वर्ष	वसूली प्रतिशत
1992-93	41*
1993-94	44*
1994-95	48*

*अनन्तिम

(ग) और (घ) नाबार्ड ने यह भी सूचित किया है कि दिनांक 31.3.95 को स्थिति के अनुसार, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल संचयी घाटा 1691.71 करोड़ रुपया था। इन घाटों के लिए ऊंची स्थापना लागत, कम कारोबार, कम मार्जिन और कम वसूली मुख्य रूप से उत्तरदायी थे।

(ङ) नाबार्ड ने सूचित किया है कि उसने अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालने के संबंध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कोई सामान्य निर्देश जारी नहीं किया है। तथापि, उसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जो विशिष्ट हवाले दिए हैं, उनके संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए बताया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का बोर्ड ही ऐसा प्राधिकरण है, जो प्रायोजक बैंकों से परामर्श करके बट्टे खाते के मामलों पर निर्णय ले सकता है। ऐसा निर्णय समुचित सुरक्षा तथा बैंकों के हित को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त वाणिज्यिक निर्णय पर आधारित होना चाहिए।

Committee to Suggest Criterion for Measuring Rate of Inflation

2293. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to ask a committee of experts to suggest a revised criterion for measuring the rate of inflation in the country;

(b) whether the committee would also lay down the guidelines or constructing a running index of retail prices; and

(c) whether estimates exist of the rate of inflation that has taken place in the country measured in terms of movement in retail prices?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes Sir, the Ministry of Industry has set up a high level expert group to revise the current series of Wholesale Price Index.

(b) No, Sir.

(c) There is no single composite series of index numbers currently available to reflect retail price changes at all India level. However, there are four distinct Consumer Price Index Series available to reflect retail prices changes for (i) industrial workers; (ii) urban non-manual employees; (iii) agricultural labourers; and (iv) rural labourers.

Constant loss by various public undertakings

2294. SHRI G. PRATHAPA REDDY: Will
the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether various public undertakings under his Ministry are incurring constant loss for the last several years;